विश्वविद्यालय रैंकिंग प्रणाली में बदलाव की ज़रूरत

विश्वविद्यालयों की अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग के पैमानों में बदलाव की आवश्यकता महसूस की जा रही है ताकि उन्हें और अधिक तार्किक बनाया जा सके। फ्रेंच राष्ट्रपति निकोलस सरकोज़ी इस बात को लेकर परेशान हैं कि उनके विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में काफी पीछे हैं। इसके चलते ही उन्होंने फ्रेंच विज्ञान और उच्च शिक्षा संस्थान को निर्देश दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में प्रथम20 में कम से कम 2 और प्रथम 100 में कम से कम 10 फ्रेंच संस्थान होने चाहिए। और सरकोज़ी अकेले नहीं हैं। विश्वविद्यालयों की रेटिंग बढ़ाने को लेकर दुनिया भर में चिंता है।

जैसे जिओ टांग विश्वविद्यालय, शंघाई ने2003 में एक प्रोग्राम शुरू किया जिसमें देश के विश्वविद्यालयों की तुलना दुनिया के विश्वविद्यालयों से करना तय हुआ। 2004 में टाइम्स हायर एजुकेशन मैग्ज़ीन की स्थापना भी इसी तरह का एक प्रयास था।

इस तरह की रैंकिग सामान्यतया कुछ मापदण्डों को संयोजित करके बनाई जाती है। जैसे, विश्वविद्यालय का शोध प्रकाशन और उनकी प्रतिष्ठा। अलबत्ता, अनेक आलोचकों ने इस ओर इशारा किया है कि ऐसे आकलनों में पूरा ध्यान शोध कार्य पर होता है और अन्य महत्त्वपूर्ण पक्षों को नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है। जैसे, अन्य शैक्षिक कार्य। इनमें इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया जाता कि कोई विश्वविद्यालय अपने विद्यार्थियों को तार्किक रूप से सोचने और नवाचार के लिए कितना तैयार कर पाता है।

इस तरह के मूल्यांकनों में जैव चिकित्सा जैसे क्षेत्र में काम कर रहे संस्थानों को सराहा जाता है क्योंकि इस विषय के शोध पत्रों को ज़्यादा उद्धरित किया जाता है। दूसरी ओर, इंजीनियरिंग और सामाजिक विज्ञान से जुड़े संस्थानों को कम करके आंका जाता है। सवाल तो इस बात पर भी है कि क्या विश्वविद्यालय वास्तव में मूल्यांकन की इकाई हैं। इस संदर्भ में अलग-अलग विभाग ज़्यादा प्रासंगिक हैं।

मगर जिन विश्वविद्यालयों को अच्छी रैंक मिलती है वे इसकी समीक्षा करने की बजाय इसका ढिंढोरा पीटते हैं। इसके चलते इस रैंकिंग को और बढ़ावा मिलता है। नीतिकार व मीडिया भी इसकी गहराई में नहीं जाते।

सुखद बात यह है कि अब रैंकिंग पद्धति में ऐसे कुछ बिंदुओं को शामिल करना शुरू हुआ है। इन प्रयासों से यह पद्धति बहुमुखी बनेगी और शोध, अध्यापन एवं स्थानीय व औद्योगिक जुड़ाव को भी स्थान मिलेगा। अब इस बात पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि एक जैसे संस्थानों की तुलना की जाए। और सबसे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन तो यह हुआ है कि अब एक रैंकिंग की बजाय विश्वविद्यालयों का डैटा बेस प्रकाशित किया जाए ताकि व्यक्ति प्रासंगिक जानकारी देख सकें।

रैंकिंग की दिक्कतों के बावजूद इन्होंने विश्वविद्यालय की सूचनाओं और आंकड़ों को पारदर्शिता एवं ज़िम्मेदारी निर्धारित करने के औज़ार की तरह प्रयुक्त किया है। शासन और संस्थान उपलब्ध आंकड़ों को और विस्तार देकर इसमें मदद कर सकते हैं। वे विश्वविद्यालयों के मूल कार्यों के साथ ही अर्थव्यवस्था और समाज पर उनके प्रभावों को मापने के बेहतर रास्ते तलाश कर और भी मदद कर सकते हैं।

विश्वविद्यालयों को भी सतर्क रहना होगा कि वे अपनी नीतियों को रैंकिग से ज़्यादा प्रभावित न होने दें। ***(स्रोत फीचर्स)***